SHRI AJIT PANJA: Therefore, this was considered about paying the whole duty at the raw material stage and nothing being paid at the end. The hon. Member must appreciate that when I purchase raw material, if the entire excise duty is to be collected then and there, then, the money that is available in the hand of the small scale unit for the purpose of doing other works will be limited. That is why it is being taken out in phases at the raw material stage, giving that notional credit at the end.

Threat to pre-historic sites due to the construction of dams across the Narmada river

*485. SHRI KALPNATH RAI:†
SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there are some schemes under execution for constructing dam across the Narmada river;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that some experts have observed that those dams are posing a threat some pre-historic sites, and

(d) if so, what is Government's reaction to these observations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) Narmada Sagar (Indira Sagar) Project in Madhya Pradesh envisaging annual irrigation of 1.69 lakh hectares with installed power capacity of 1000 MW and Sardar Sarovar Project in Gujarat envisaging annual irrigation of 17.92 lakh hectares with installed power capacity of 1450 MW. Sardar Sarovar Project also provides for conveying water to irrigate 0.73 lakh hectares in Rajasthan.

(c) and (d) The project already provides for removal and re-installation of ancient or historical monuments and archaeological remains likely to be affected by submergence.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभापति महोदय, परियोजना में जलमग्नता द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना वाले प्राचीन अथवा एतिहासिक स्मारक कौन-कौन से हैं, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह सूचित किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर जांच होती रही है और मध्यप्रदेश के देवास, खंडवा तथा होशंगाबाद जिलों में स्थित जलमग्न क्षेत्र में अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण एवं दस्तावेज कार्यक्रम पहले भी प्रारम्भ किए कार्य प्रगति पर है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि 30 साइट्स एंड मोनूमेंट्स जो हैं वे नर्मदा वैली में मध्य प्रदेश में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आते हैं। उसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश में मंडलेश्वर मंदिर और शहर है जो कि बच जायेंगे, रिजर्वायर का जो जल-मग्न स्तर है उसके नीचे उसको रखा गया है। लेकिन गुजरात में सूर्यनेश्वर मंदिर है जो 6 किलो मीटर अपस्ट्रीम में पड़ता है उसको खतरा है और वह डूब जायेगा। हम्फेश्वर मंदिर जो 46 किलो मीटर अपस्ट्रीम में है वह भी डैम के अन्तर्गत पड़ता है उसको भी खतरा है। लेकिन साथ ही साथ में यह बताना चाहूंगी कि इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत जो जंगा है वहां पर मुगल ओल्ड फोर्ट है वह पानी से थोड़ा घिर जायेगा अवश्य और एक द्वीप के रूप में बन जायेगा। वह बहुत डूबाव के क्षेत्र में नहीं पड़ेगा नदी के किनारे-किनारे है, यह योजना ऐसी है जो लिमिटेड है और इसमें कोई खतरा नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि 30 ऐसे हैं साइट्स और पुरातत्व विभाग वाले

उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं । इसकी सूची मैंने इनको बता दी है ।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पुरातत्व विभाग ने इन प्राचीन एतिहासिक स्मारकों के जलमग्न होने के कारण सरकार के पास कोई प्रोटेस्ट दिया है ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट उनका नहीं आया है और न इसकी कोई जानकारी है बल्कि माननीय सदस्य को सम्भवतः यह मालूम होगा कि एक अथोरिटी, नर्मदा अथोरिटी और रिव्यू कमेटी जो बनाई गई है, वह एक ऐसी कमेटी है, जिसमें कि सभी संबंधित प्रांतों के मुख्य मंत्री भी रहते हैं, पर्यावरण विभाग के मंत्री भी रहते हैं वाटर रिसोर्सेज के मंत्री भी रहते हैं और आर्कलोजी, जो कल्चर के अन्दर आता है, उनके भी बड़े पदाधिकारी एक सब कमेटी में रहते हैं। समय-समय पर शिकायतें सुनने का प्रावधान है और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात होती है तो उनकी नजर में लायी जाती है । लेकिन राज्य सरकार का जो सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग है और जो भारत सरकार का हैं, दोनों के समन्वय से यह काम हो रहा है । इसमें पूरी निगरानी रखी जा रही है । 1987 मे एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी, जिसमें दोनों प्रांतों का जो झमेला था, वह तय हो गया था । उसके बाद से काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण का काम कब तक पूरा हो जाएगा और जो प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक डूब में आ रहे हैं, उसके लिये सरकार क्या कोई प्रीकॉशन ले रही है ? क्या इससे कोई धार्मिक भावनायें उभरेंगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, इन्होंने इसका समय पूंछा है कि कितने समय में पूरा होगा ?... **(व्यवधान)**

ठाकुर जगतपाल सिंह : कब सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती कृष्णा साही : तकरीबन दस वर्ष का इसमें प्रोवीजन है... **(व्यवधान)**

ठाकुर जगतपाल सिंह : सर्वेक्षण जो कर रहे हैं आप, वह कब तक पूरा होगा ?

श्रीमती कृष्णा साही : सर्वेक्षण का पूछ रहे हैं, तो अभी सर्वेक्षण का काम एक फेज में हुआ है और प्रगति पर है, बाकी एक साल और लगेगा तो सम्भवतः पूरा हो जाएगा ।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति महोदय, नर्मदा की इस योजना में मराठों के विख्यात नेता बाजीराव पेशवा की रावरखेड़ा स्थित समाधि डूबने वाली है । महाराष्ट्र की ओर से यह निरन्तर मांग की गई है कि इस समाधि को उसी स्थान पर ऊपर उठाकर पर्यटन स्थल में रूपांतरित किया जाय । तो क्या इस प्रकार की मांग पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है और गौर कर रही है तो इसका निर्णय कब तक होगा ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, इसका संबंध तो हमारे जल-संसाधन मंत्रालय से नही है, जो मांग इनकी हुयी है, उसकी सूची मैंने इनको बताई है । और न किसी की ओर से विरोध अभी प्राप्त नहीं हुआ है हम लोगों के पास । ऐसी मांग की हमारे पास कोई दरखास्त नहीं है ।

SHRI K. MOHANAN: Everybody is sentimental on religious or environmental grounds and so on and so forth, but the point is that this country is still in deficit in power generaton. The cheapest source of energy is by hydro projects. When the Government has cleared the Narmada project, as far as my State, Kerala, is concerned, which is fully depending on hydro-electric projects, its nine projects are still pending with the Government for the last nine years.

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI K. MOHANAN: My question is keeping apart the religious and environmental considerations, whether the Government will, in the interest of the future of this country, clear at least some major projects...Is the time over, Sir?

MR CHAIRMAN: It will be over, if you go on askng like this. I am only helping you.

SHRI K. MOHANAN: Anyway, I will not get the answer since the time is over.

MR. CHAIRMAN: Not yet.

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, यह केरल का तो प्रश्न नहीं है । इसका संबंध है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से ।

SHRI ARUN SINGH: Why is the Ministry of Water Resources handling this question?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Clearance of Pooyankutty Hydel Project

*483. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Pooyan Kutty Hydel Project of Kerala has been cleared by his Ministry:

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) by when the project is likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. A. ANSARI): (a) to (c) Pooyankutty Hydel Project was accorded approval from environmental angle in June, 1985.

The project involves loss of 3001.8 ha of semi evergreen forest and requires approval under the Forest (Censervation) Act, 1980 for diversion of forest land. Consideration of such clearance from forest angle can be taken up only when the complete details sought from the State Government are received. It is not possible to indicate whether or when the project will be cleared.

External economic relations

*486. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring about a change in external economic relations; if so, what are the details thereof; and

(b) whether Government propose to link repayment of loans due to any country with the percentage of export earnings from that country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) No, Sir.

Review of the role of Export Houses

*487. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to review the role of export houses in order to encourgae them to take a more active role in exports; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) The role of export houses has been reviewed in the context of the formulation of the new Import-Export Policy with effect from 1st April, 1988. Details of the changes made in the policy in respect of Export Houses will be known after the new Policy is laid on the Table of the House on 30th March, 1988.